Dainik Jagran, Alipur, 05/09/2025
Page No: 17, Size: 13.92cm × 16.80cm

मुंबई के निकट केवल मुस्लिम समुदाय के लिए बनाया जा रहा आवासीय परिसर

ओमप्रकाश तिवारी ● जागरण

मुंबई : मुंबई के निकट रायगढ़ जिले में एक ऐसा आवासीय परिसर बनाने का विज्ञापन दिया जा रहा है, जो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए होगा। इस विज्ञापन पर कुछ स्थानीय संगठनों ने आपत्ति जताई है। मानवाधिकार आयोग ने भी इसका स्वतः संज्ञान लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

रायगढ़ के कर्जत क्षेत्र स्थित नेरल गांव के पास प्रस्तावित इस आवासीय परिसर के आडियो-वीडियो विज्ञापन में एक विशेष समुदाय में पहने जाने वाले वस्त्रों को पहने एक युवती यह कहती दिखाई दे रही है कि जब सोसायटी में सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता हो तो क्या वह सही है।

योजना का आडियो-वीडियो विज्ञापन सामने आने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान

'सुकून एम्पायर' में समान विचारों वाले परिवार एक साथ रह सकते हैं। यहां बच्चे बिल्कुल 'हलाल' वातावरण में पल-बढ़ सकते हैं। यह निवेश सिर्फ आपके पैसों को नहीं, बल्कि आपके परिवार के भविष्य को भी सुरक्षित रखेगा। इस विज्ञापन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि हम महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर यह पूछ रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में क्या मुसलमानों के लिए अलग बस्ती बसाने की अनुमति दी गई है। कानूनगो कहते हैं कि मामला केवल अलग टाउनशिप बनाने का नहीं है। यह विज्ञापन इस तरीके से किया जा रहा है कि मुसलमानों को असहिष्णुता का सामना करना पड़ रहा है।

हिंदू अपने फ्लैट और घर कम कीमतों पर बेचकर पलायन करने को मजबूर : आसपास रहने वाले लोगों का भी कहना है कि नेरल ग्राम पंचायत के आसपास एक विशेष समुदाय के लिए आवासीय परिसर का निर्माण कर वहां हिंदुओं की आबादी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कारण नेरल में रहने वाले हिंदुओं को अपने फ्लैट एवं घर बाजार भाव से काफी कम कीमतों पर बेचकर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसे रोका जाना चाहिए।

DJ Rashtriya Sanskaran, New Delhi, 05/09/2025
Page No: 6, Size: 25.11cm × 11.22cm

मुंबई के पास सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए बनाया जा रहा आवासीय परिसर

ओमप्रकाश तिवारी ● जागरण

- विज्ञापन में कहा, यहां समान विचारों वाले परिवार साथ रह सकते हैं, बच्चे 'हलाल' वातावरण में पल-बढ़ सकते हैं
- आडियो-वीडियो विज्ञापन सामने आने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया स्वत: संज्ञान

मुंबई : मुंबई के निकट रायगढ़ जिले में एक ऐसा आवासीय परिसर बनाने का विज्ञापन दिया जा रहा है, जो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए होगा। इस विज्ञापन पर कुछ स्थानीय संगठनों ने आपत्ति जताई है। मानवाधिकार आयोग ने भी इसका स्वतः संज्ञान लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

रायगढ़ के कर्जत क्षेत्र स्थित नेरल गांव के पास प्रस्तावित इस आवासीय परिसर के आडियो-वीडियो विज्ञापन में एक विशेष समुदाय में पहने जाने वाले वस्त्रों को पहने एक युवती यह कहती दिखाई दे रही है कि जब सोसायटी में सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता हो तो क्या वह सही है। 'सुकून एम्पायर' में समान विचारों वाले परिवार एक साथ रह सकते हैं। यहां बच्चे बिल्कुल 'हलाल' वातावरण में पल-बढ़ सकते हैं। यह निवेश सिर्फ आपके पैसों को नहीं, बल्कि आपके परिवार के भविष्य को भी सुरक्षित रखेगा।

इस विज्ञापन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि हम महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर यह पूछ रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में क्या मुसलमानों के लिए अलग बस्ती बसाने की अनुमति दी गई है। कानूनगो कहते हैं कि मामला केवल अलग टाउनशिप बनाने का नहीं है। यह विज्ञापन इस तरीके से किया जा रहा है कि मुसलमानों को असहिष्णुता का सामना करना पड़ रहा है और मुसलमान खुद को सुरक्षित करने के लिए अलग जगहों पर जाना चाहते हैं। ये 'नेशन विद इन द नेशन' (राष्ट्र के अंदर एक और राष्ट्र) के सिद्धांत जैसा है।

कानूनगो कहते हैं कि आज वे लोग अलग बस्ती की बात कर रहे हैं। कल कहेंगे कि हमें डाक्टर भी मुसलमान चाहिए। परसों कहेंगे कि हमको पुलिस मुसलमान चाहिए। फिर कहेंगे कि हमको बस ड्राइवर मुसलमान चाहिए। और एक दिन यह कहेंगे कि हमको महाराष्ट्र में एक अलग राज्य चाहिए। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत संविधान के अनुसार सेक्युलर सिद्धांतों पर चलने वाला राष्ट्र है। इसलिए, सरकार को नोटिस जारी कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

आसपास रहने वाले लोगों का भी कहना है कि नेरल ग्राम पंचायत के आसपास एक विशेष समुदाय के लिए आवासीय परिसर का निर्माण कर वहां हिंदुओं की आबादी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कारण नेरल में रहने वाले हिंदुओं को अपने फ्लैट एवं घर बाजार भाव से काफी कम कीमतों पर बेचकर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसे रोका जाना चाहिए।

DJ Rashtriya Sanskaran, New Delhi, 05/09/2025
Page No: 7, Size: 5.19cm × 18.23cm

ट्रांसजेंडरों से भेदभाव खत्म करने पर जोर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष जस्टिस (सेनि) वी. रामसुब्रमण्यम ने ट्रांसजेंडरों के साथ व्यवस्थागत भेदभाव खत्म करने और उनके अनुभवों को बेहतर बनाने पर जोर देते हुए कहा कि समाज उन लोगों को स्वीकारने में संघर्ष कर रहा है जो पुरुष और महिला के द्विभाजन में फिट नहीं बैठते। जस्टिस रामासुब्रमण्यम ने गुरुवार को ट्रांसजेंडरों के अधिकार पर एनएचआरसी द्वारा आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि सौभाग्य से भारत ट्रांस व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता देने में कई अन्य देशों से बहुत आगे है। भले ही हम आदर्श स्थिति तक नहीं पहुंच पाए हों लेकिन हम निश्चित रूप से काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह बात दुनिया भर के समाजों को अभी स्वीकारने में कठिनाई हो रही है और इसका परिणाम है कि ट्रांसजेंडर लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र, स्कूलों, रोजगार और आवास के साथ-साथ शौचालयों तक पहुंच में व्यापक भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

Times of India, Mumbai, 05/09/2025
Page No: 3, Size: 8.39cm × 53.23cm

NHRC probe in township at Karjat after plaint

B B Nayak

Navi Mumbai: The National Human Rights Commission (NHRC) has launched an investigation into a complaint filed under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, accusing Maharashtra Real Estate Regulatory Authority of approving a 'Halal Lifestyle Township' in Karjat exclusively for the Muslim community. According to NHRC, the complainant stated that the project is being promoted as a residential enclave specific to one religion, which he claims promotes communal segregation and violates constitutional guarantees of equality and non-discrimination.

Priyank Kanoongo, member presiding over the NHRC bench, noted that the Commission had issued a notice to the state chief secretary requesting an inquiry. He said a report was sought within two weeks of receipt of the notice. MahaRERA was also asked to detail provisions under which it granted a licence for a township based on religion.

The township was featured in a promotional video that emphasised community living, shared values, and a safe environment for children and elders. The controversy intensified when Kanoongo shared the video and criticised the project.

Kanoongo's remarks triggered a debate. Critics of the township accused it of promoting segregation, while others pointed out that Muslims often face discrimination in housing, leaving them with limited options. Several on social media argued that many residential societies deny homes to Muslims, and projects like this emerged as a response to such exclusion.

Political & Business Daily, Bhubaneshwar, 05/09/2025
Page No: 7, Size: 28.89cm × 16.51cm

Society struggling to accept humans who don't fit into man-woman binary: NHRC

NEW DELHI, SEP 4

INDIA is "far ahead" of several other nations in recognising the rights of transgender persons, and while the country "may not have reached an ideal level", but it has certainly advanced to a great extent in this area, NHRC Chairperson, Justice (retd) V Ramasubramanian said on Thursday.

In his address at a national conference here, he also said that there could be or that there are human beings who "do not fit into this binary of man or woman" -- is something that the societies all over, are still grappling to accept.

"The consequence of this, is that

trans people experience widespread discrimination and stigma in the health sector, schools, employment and housing as well as in accessing bathrooms," the National Human Rights Commission (NHRC) chairperson said.

Centered on the theme "Revamping Spaces, Reclaiming Voices," the event emphasises "the immediate need to tackle systemic discrimination, uplift lived experiences, and promote meaningful inclusion for transgender persons in all areas of life", the NHRC said.

The rights panel chief began his address by quoting some texts from the Upanishads, which underline that the God pervades in all humans, and all living and non-living beings. If India is a country where the discourse on equality was taken to such great heights by the Upanishads, and if it is the philosophy of the Upanishads that every unit of creation is God's manifestation, "can some units of such creation be discriminated against by others," the NHRC chief asked.

Hamara Mahanagar, Mumbai, 05/09/2025
Page No: 2, Size: 16.62cm × 16.01cm

'हलाल टाउनशिप' पर मानवाधिकार आयोग सख्त

NHRC ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी रिपोर्ट

महानगर संवाददाता

मुंबई

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मुंबई से सटे कर्जत में विकसित की जा रही एक टाउनशिप परियोजना को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। आयोग को मिली शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यह टाउनशिप सिर्फ एक ही धर्म (मुस्लिम समुदाय) के लिए 'हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप' नाम से प्रमोट की जा रही है। शिकायतकर्ता ने इसे धार्मिक आधार पर विभाजन और सामुदायिक अलगाव को बढ़ावा देने वाला प्रोजेक्ट बताया है। साथ ही इसे संविधान के प्रावधानों,समानता और गैर-भेदभाव के अधिकार का उल्लंघन करार दिया है। सुरक्षा और सामाजिक दृष्टिकोण से भी इस प्रोजेक्ट को लेकर चिंता जताई गई है और कहा गया है कि

यह 'कट्टरपंथी गेट्टोइजेशन' का केंद्र बन सकता है। आयोग ने इसे मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला मानते हुए महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि शिकायत की गहन जांच कर 2 हफ्तों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाए। यह स्पष्ट किया जाए कि RERA (मुंबई, महाराष्ट्र) ने धार्मिक आधार पर इस परियोजना को लाइसेंस/अनुमति कैसे प्रदान की और रिपोर्ट की एक प्रति आयोग को ईमेल से भी भेजी जाए। मानवाधिकार आयोग की बेंच, जिसकी अध्यक्षता सदस्य प्रियंक कानूनगो कर रहे हैं, ने इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम,1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान में लिया है। बता दें कि आयोग के समक्ष दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यह टाउनशिप विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लिए प्रचारित और विकसित की जा रही है।

Nai Duniya, Bhopal, 05/09/2025
Page No: 8, Size: 15.56cm × 24.42cm

'मछली' को छोड़ने की 'सिफारिश' का सवाल, गरमाई राजनीति

नवदुनिया प्रतिनिधि, सीधी : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने एक दिन पहले एक्स हैंडल पर पोस्ट करके जिस जैनेंद्र पाठक के अपने दिल्ली आवास पर पहुंचने का जिक्र करके आशंका जताई कि वह शायद मछली गिरोह के मामले में सिफारिश की कोशिश कर रहा था, उसे लेकर अब मप्र की राजनीति गरमा गई है।

दरअसल, सीधी जिले में प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल ने यह जैनेंद्र पाठक सिंहावल से भाजपा विधायक विश्वामित्र पाठक का भतीजा है और उसके पूरे देश में भाजपा नेताओं के साथ नजदीकी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का करीबी भी माना जाता है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर असम, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी तस्वीरें हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं के साथ उनका उठना-बैठना है। पटेल ने यह आरोप फेसबुक पर पोस्ट करके लगाया। सवाल उठाया कि क्या जैनेंद्र पाठक ड्रग्स, दुष्कर्म, लव जिहाद जैसे गंभीर आरोपों में फंसे 'मछली' को छोड़ देने की सिफारिश कर रहा था।

कमलेश्वर पटेल

- **कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने प्रियंक कानूनगो से जैनेंद्र पाठक की मुलाकात पर टिप्पणी की**

पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव मंच से 'मछली' का घर गिरवाकर नैतिकता की बातें करते हैं तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के विधायक का रिश्तेदार मानवाधिकार आयोग में मिठाई और सिफारिशें लेकर कुख्यात आरोपित 'मछली' को बचाने पहुंचता है। यह भाजपा का दोहरा चरित्र है। कमलेश्वर ने कहा कि भाजपा सरकार मछली के साथ जैनेंद्र पाठक के विरुद्ध भी कार्रवाई करना चाहिए।

Rajasthan Patrika, Bhopal, 05/09/2025
Page No: 6, Size: 7.51cm × 11.77cm

शराब दुकान पर कार्रवाई नहीं

मानवाधिकार आयोग ने कलेक्टर को जारी किया समन

भोपाल. अवैध शराब दुकान-कम-बार पर कार्रवाई नहीं करने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और आबकारी आयुक्त को समन जारी कर 3 अक्टूबर को मानवाधिकार आयोग के केंद्रीय कार्यालय, दिल्ली में आवश्यक प्रतिवेदन सहित उपस्थित होने को कहा है। अरेरा कॉलोनी में आवासीय भूखंड पर अवैध शराब दुकान-कम-बार के मामले में यह नोटिस जारी हुई।

Free Press Journal

‘Machhli’ Gang Aide Visited Me, Says NHRC Member Priyank Kanoongo

https://www.freepressjournal.in/bhopal/machhli-gang-aide-visited-me-says-nhrc-member-priyank-kanoongo

Wednesday, September 03, 2025, 09:35 PM IST

‘Machhli’ family attempted to influence National Human Rights Commission (NHRC) member Priyank Kanoongo

Bhopal (Madhya Pradesh): In a bid to stop ongoing investigations against them, a man allegedly connected to the notorious ‘Machhli’ family attempted to influence National Human Rights Commission (NHRC) member Priyank Kanoongo.

Taking to X (previously Twitter), Kanoongo said on Wednesday that Shariq Machhli used his associate, a property dealer named Jainendra Pathak, to reach out to him.

Pathak allegedly visited Kanoongo at his official residence in Delhi earlier in the day, introducing himself as a resident of Madhya Pradesh and a business partner of Shariq.

Citing heavy financial losses, he urged Kanoongo to forgive Shariq. However, Kanoongo rebuked him and sent him away. Before leaving, Pathak allegedly left behind a box of sweets at the gate, which was seized by police after a complaint.

Kanoongo went on to clarify that Shariq is under probe for allegedly drugging and raping Hindu women, recording videos to blackmail them, and forcing their religious conversion to Islam. He is also accused of encroaching upon ponds traditionally reserved for the fishing rights of marginalised Hindu communities, such as Kevat and Manjhi. Kanoongo asserted that investigations would continue despite such pressure tactics.

Notably, Shariq is the uncle of jailed gangster DJ Yaseen Machhli, the kingpin of a drugs and firearms syndicate busted by the Bhopal Crime Branch. Authorities have also demolished illegal constructions of the Machhli family on encroached government land at AnantpuraKoktain two separate demolition drives.

Police have taken cognizance of the intimidation attempt, and further inquiry is underway.

Collector gets demarcation report of Animal Husbandry land

In the wake of the action against the notorious ‘Machhli’ family, the demarcation report of an Animal Husbandry land was submitted to Collector Kaushalendra Vikram Singh on Wednesday.

The report, prepared by a team of three revenue inspectors and 11 patwaris, mentions large-scale encroachment on six acres of land belonging to the department in the AnantpuraKokta area.SDM Ravish Srivastava and Tehsildar Saurabh Verma presented the findings.

The Animal Husbandry department will soon issue notices to the identified encroachers. However, officials are tight-lipped and have not yet disclosed the full details of the report.

Meanwhile, official sourcesclaimed that more than 40 buildings, 30 shops, a petrol pump, a school, and multiple residential colonies have been built illegally on the plot.

The largest encroachment was a private colony, comprising many residences. Even the municipal corporation was found occupying part of the land, and officials are considering offering alternate land to the department.

Members of the Machhli family face cases related to drugs and sexual assault. The administration demolished seven illegal structures linked to them on July 30 and August 21.

Suspecting encroachment on its land, the Animal Husbandry department had requested the demarcation, which confirmed the violations. Around 20 people, including the Machhli family, were issued notices and asked to be present during the survey.

Jagran

'समाज उन लोगों को स्वीकारने में संघर्ष कर रहा जो...', ट्रांसजेंडर्स पर NHRC अध्यक्ष का बड़ा बयान

https://www.jagran.com/news/national-nhrc-chair-calls-for-ending-discrimination-against-transgenders-in-india-24035912.html

Thu, 04 Sep 2025 08:34 PM (IST) Swaraj Srivastava

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम ने ट्रांसजेंडरों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज आज भी ट्रांसजेंडरों को स्वीकार करने में संघर्ष कर रहा है जिससे उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष जस्टिस (सेवानिवृत) वी. रामसुब्रमण्यम ने गुरुवार को ट्रांसजेंडरों के साथ व्यवस्थागत भेदभाव खत्म करने और उनके अनुभवों को बेहतर बनाने पर जोर देते हुए कहा कि समाज उन लोगों को स्वीकारने में संघर्ष कर रहा है जो पुरुष और महिला के द्विभाजन में फिट नहीं बैठते।

जस्टिस रामसुब्रमण्यम ने कहा कि समाज आज भी यही सोचता है कि केवल पुरुष और महिलाएं ही मानव जाति का निर्माण करते हैं। यह बात दुनिया भर के समाजों को अभी स्वीकारने में कठिनाई हो रही है और इसका परिणाम है कि ट्रांसजेंडर लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र, स्कूलों, रोजगार और आवास के साथ-साथ शौचालयों तक पहुंच में व्यापक भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

एनएचआरसी द्वारा आयोजित था कार्यक्रम

जस्टिस रामासुब्रमण्यम ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार पर एनएचआरसी द्वारा आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के संबोधन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सौभाग्य से भारत ट्रांस व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता देने में कई अन्य देशों से बहुत आगे है। भले ही हम आदर्श स्थिति तक नहीं पहुंच पाए हों लेकिन हम निश्चित रूप से काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। ॉ

इस अवसर पर एनएचआरसी के सेकेट्री जनरल भरत लाल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव अमित यादव, के अलावा ट्रांस व्यक्तियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। सम्मेलन में ट्रांस व्यक्तियों के अधिकारों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर ट्रांस व्यक्तियों के आश्रय घर गरिमा गृहों की स्थिति पर एक रिपोर्ट भी जारी हुई।

ABP Live

Halal Township: देश की आर्थिक राजधानी में हलाल टाउनशिप से मचा बवाल, NHRC ने महाराष्ट्र सरकार से 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

https://www.abplive.com/news/india/halal-township-in-mumbai-nhrc-takes-cognizance-summons-report-from-maharashtra-government-in-2-weeks-ann-3006608/amp

04 Sep 2025 08:29 AM (IST) Santosh Singh

Halal Township in Mumbai: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसे गंभीर मानवाधिकार का उल्लंघन मानते हुए महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है.

मुंबई के पास करजत इलाके में प्रस्तावित Halal Lifestyle Township प्रोजेक्ट को लेकर दी गई एक शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया है. आयोग के समक्ष दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यह टाउनशिप विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लिए प्रचारित और विकसित की जा रही है, जो सामुदायिक अलगाव (communal segregation) को बढ़ावा देती है और संविधान में समानता एवं भेदभाव विरोधी प्रावधानों का उल्लंघन है.

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भेजी गई शिकायत में शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि इस प्रकार की परियोजना न केवल सामाजिक और संवैधानिक मानकों के विपरीत है, बल्कि सुरक्षा और सामाजिक दृष्टि से भी खतरनाक साबित हो सकती है. आरोप है कि यह क्षेत्र भविष्य में कट्टरपंथी क्षेत्र में बदल सकता है.

महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस

आयोग ने शिकायत को प्रथम दृष्टया गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है. नोटिस में दो हफ्तों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने और यह साफ करने के लिए कहा गया है कि रेरा (RERA) ने किन प्रावधानों के तहत इस तरह की अनुमति या लाइसेंस जारी किया.

प्रियांक कानूनगो ने विज्ञापन को बताया विष व्यापन

आयोग की बेंच की अध्यक्षता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने की. उन्होंने कहा कि मामले में उठाए गए आरोप अगर सही पाए जाते हैं तो यह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का उदाहरण होगा और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यह विज्ञापन नहीं विष व्यापन है. मुंबई के पास करजत इलाके में केवल मुसलमान मज़हब वालों के लिए हलाल लाइफ़ स्टाइल वाली टाउनशिप बनाई जा रही है. यह Nation Within The Nation है. महाराष्ट्र सरकार को नोटिस किया जा रहा है.

ABP Live

Mumbai: 'हलाल टाउनशिप' पर मानवाधिकार आयोग सख्त, NHRC ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी रिपोर्ट

https://www.abplive.com/states/maharashtra/mumbai-karjat-religious-based-township-nhrc-maharashtra-government-report-ann-3006775

04 Sep 2025 06:40 PM (IST) Suraj Ojha

Maharashtra News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुंबई के कर्जत में "हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप" को लेकर शिकायत पर महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मुंबई से सटे कर्जत में विकसित की जा रही एक टाउनशिप परियोजना को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है. आयोग को मिली शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यह टाउनशिप सिर्फ एक ही धर्म (मुस्लिम समुदाय) के लिए "हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप" नाम से प्रमोट की जा रही है.

शिकायतकर्ता ने इसे धार्मिक आधार पर विभाजन और सामुदायिक अलगाव को बढ़ावा देने वाला प्रोजेक्ट बताया है. साथ ही इसे संविधान के प्रावधानों, समानता और गैर-भेदभाव के अधिकार का उल्लंघन करार दिया है.

2 हफ्तों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट की मांग

सुरक्षा और सामाजिक दृष्टिकोण से भी इस प्रोजेक्ट को लेकर चिंता जताई गई है और कहा गया है कि यह "कट्टरपंथी गेट्टोइजेशन" का केंद्र बन सकता है. आयोग ने इसे मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला मानते हुए महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है.

साथ ही निर्देश दिया गया है कि शिकायत की गहन जांच कर 2 हफ्तों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाए. यह स्पष्ट किया जाए कि RERA (मुंबई, महाराष्ट्र) ने धार्मिक आधार पर इस परियोजना को लाइसेंस/अनुमति कैसे प्रदान की और रिपोर्ट की एक प्रति आयोग को ईमेल से भी भेजी जाए.

1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान में लिया

मानवाधिकार आयोग की बेंच, जिसकी अध्यक्षता सदस्य प्रियंक कानूनगो कर रहे हैं, ने इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान में लिया है. बता दें, आयोग के समक्ष दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यह टाउनशिप विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लिए प्रचारित और विकसित की जा रही है.

यह सामुदायिक अलगाव (Communal Segregation) को बढ़ावा देती है और संविधान में समानता एवं भेदभाव विरोधी प्रावधानों का उल्लंघन है. शिकायत में शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि इस प्रकार की परियोजना न केवल सामाजिक और संवैधानिक मानकों के विपरीत है, बल्कि सुरक्षा और सामाजिक दृष्टि से भी खतरनाक साबित हो सकती है. आरोप है कि यह क्षेत्र भविष्य में कट्टरपंथी क्षेत्र में बदल सकता है.

Lokmat Times

NHRC chief bats for fighting discrimination against Trans people

https://www.lokmattimes.com/national/nhrc-chief-bats-for-fighting-discrimination-against-trans-people/

September 4, 2025 21:45 IST

New Delhi, Sep 4 Calling for greater social acceptance, NHRC Chairperson Justice V. Ramasubramanian said on Thursday that....

New Delhi, Sep 4 Calling for greater social acceptance, NHRC Chairperson Justice V. Ramasubramanian said on Thursday that Trans people experience widespread discrimination and stigma in the health sector, schools, employment and housing, as well as in accessing washrooms.

Addressing a day-long National Human Rights Commission (NHRC) conference on the 'Rights of Transgender Persons: Revamping Spaces, Reclaiming Voices', Justice Ramasubramanian said that, fortunately, India is far ahead of several other countries in recognising the rights of transgender persons.

He said that in India, the legislative, executive and the judiciary have come together to transform the philosophy of Upanishads into a Constitutional theme and then to translate the same into a court order followed by a Parliamentary law in the shape of the Transgender Person (Protection of Rights Act, 2019).

"However, the constitutionality of Sections 4, 5, 6, 7, 12(3), 18(a) and 18(d) is currently under challenge before the Supreme Court of India. It is in this context that the NHRC is hosting this National Conference as a segment of our population estimated as per the 2011 census, to be around 4.88 lakh, cannot be left out of the mainstream," said Justice Ramasubramanian.

Ministry of Social Justice and Empowerment (MoSJE) Secretary Amit Yadav said that in line with the guiding principles in Articles 14, 15 and 16 of the Constitution, the government is committed to ensuring that nobody, including Transgender persons, is discriminated against.

Yadav said that the Government has also started skill and vocational training for them to ensure their employment as per the 2019 Act provisions, and the first batch of trained transgender persons is about to complete this training.

The government is also organising Rozgar melas for Transgender persons. More partnership with the private sector is needed for this purpose, he said.

The government is further working on revising its welfare schemes, and it is looking forward to suggestions, and funds are not a challenge.

He said their grievance redressal mechanism will be strengthened in the coming months, and the MoSJE is also working with the Department of Education to sensitise children about the issues of Transgender persons and build awareness in

an effort to collectively work towards their rights for equal opportunity, dignity and inclusivity.

An NHRC report - Transgender Persons: Revamping Spaces, Reclaiming Voices Insights from Garima Greh Shelters and Beyond - was also released.

The report emphasised on strengthening of the Garima Greh initiative, besides suggesting several key reforms.

It said that all states should activate Project Monitoring Committees (PMCs), with clear delegation of responsibilities to district officials and appointment of police focal points for transgender issues.

Timely release of funds must be ensured, along with revised allocations for food and beneficiaries, context-specific financial models for urban and rural shelters and infrastructure support through one-time grants, it said.

Staffing structures should align with market standards, with rationalised roles to prevent overburdening. Shelter heads must be empowered to assist with transgender ID card issuance through simplified, privacy-sensitive processes, it said.

Mathrubhumi

NHRC member flags 'nation within a nation' theory in religion-based township ads; vows strict action on Machhli family

https://english.mathrubhumi.com/news/india/nhrc-member-flags-nation-within-a-nation-theory-in-religion-based-township-ads-vows-strict-action-on-machhli-family-hsobtugi

04 September 2025, 07:45 PM IST

NHRC member Kanoongo flags Maharashtra Muslim settlements, investigates Bhopal Machhli family for Crimes.

Delhi/Bhopal: National Human Rights Commission (NHRC) member Priyank Kanoongo on Wednesday said that the rights panel is sending a notice to the Maharashtra government over plans to create separate settlements for Muslims in the state.

"We are issuing a notice to the Maharashtra government asking whether it is granting permission to create separate settlements for Muslims in Maharashtra, the land of Chhatrapati Shivaji Maharaj. This matter is not just about creating a separate township. The advertisement is being done in such a way that it suggests Muslims are facing intolerance and want to move to a separate place to protect themselves. This is an implementation of the 'nation within a nation' theory," Kanoongo said.

Machhli family associate approaches NHRC member

Kanoongo said that a man claiming to be a business associate of Bhopal's controversial Machhli family approached him at his New Delhi residence on Wednesday.

According to Kanoongo, the individual identified himself as Jainendra Pathak and claimed to be a real estate partner of Sharik Machhli. Pathak allegedly said he had come on behalf of the Machhli family, which is facing serious charges including drug trafficking, money laundering, and coercive religious conversions.

"The person offered me sweets he had brought, but I reprimanded him and asked him to leave. I have filed a formal complaint, following which Delhi Police detained the individual," Kanoongo posted on X.

Investigations against Machhli family intensify

Kanoongo said that the Bhopal Crime Branch has initiated investigations against Sharik Machhli and other family members for alleged involvement in the narcotics trade and exploitation of Hindu women through forced religious conversion.

"There will be no leniency. Madhya Pradesh Police will investigate the matter with utmost strictness and integrity," he said in a Hindi-language post.

Over the past few weeks, nearly a dozen members of the extended Machhli family have been booked under various charges, with several arrests already made. The investigation is being led by Bhopal's Crime Branch.

On August 21, the Bhopal district administration demolished a luxury bungalow belonging to the Machhli family, citing illegal construction on government land. Multiple properties and encroached plots linked to the family have also been seized in recent weeks.

The crackdown follows the July arrests of Shahwar Machhli and his nephew Yasin (also known as Yaseen) Machhli, accused of playing central roles in a drug syndicate allegedly operating across Madhya Pradesh.

Machhli family background

Originally from Budhwara, an old locality in Bhopal, the Machhli family began as fish brokers before relocating to Hathaikheda in the late 1970s and early 1980s. Over time, the family reportedly cultivated ties with local politicians and influential figures, allegedly shielding their expanding illegal operations. Their activities later diversified into fish farming, illegal mining, land grabbing, and, bythe late 1990s, narcotics and arms smuggling.

Times of India

NHRC probe into Karjat township project

https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/nhrc-probe-into-karjat-township-project/articleshow/123702683.cms

Sep 4, 2025, 09.24 PM IST

Navi Mumbai: The National Human Rights Commission (NHRC) has launched an investigation into a complaint filed under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, accusing Maharashtra Real Estate Regulatory Authority of approving a 'Halal Lifestyle Township' in Karjat exclusively for the Muslim community. According to NHRC, the complainant stated that the project is being promoted as a residential enclave specific to one religion, which he claims promotes communal segregation and violates constitutional guarantees of equality and non-discrimination.

Priyank Kanoongo, member presiding over the NHRC bench, noted that the Commission had issued a notice to the state chief secretary requesting an inquiry. He said a report was sought within two weeks of receipt of the notice. MahaRERA was also asked to detail provisions under which it granted a licence for a township based on religion.

The township was featured in a promotional video that emphasised community living, shared values, and a safe environment for children and elders. The controversy intensified when Kanoongo shared the video and criticised the project.

Kanoongo's remarks triggered a debate. Critics of the township accused it of promoting segregation, while others pointed out that Muslims often face discrimination in housing, leaving them with limited options. Several on social media argued that many residential societies deny homes to Muslims, and projects like this emerged as a response to such exclusion.

Deccan Herald

NHRC seeks report from Maharashtra government on Virar building collapse

https://www.deccanherald.com/india/maharashtra/nhrc-seeks-report-from-maharashtra-government-on-virar-building-collapse-3711358

04 September 2025, 08:20 IST Mrityunjay Bose

'The NHRC has taken suo motu cognizance of media reports on this. Reportedly, the building was unauthorised and constructed more than a decade back,' they said.

Mumbai: The National Human Rights Commission has sought a report from the Maharashtra government on the building collapse in Virar in Palghar district near Mumbai, which claimed 17 lives.

Last week, on 27 August, Ramabai Apartment, a four-storied structure located between Chamunda Nagar and Vijay Nagar on Narangi Road in Virar-East area of Vasai taluka in Palghar district, claimed 17 lives and injured several others.

"The NHRC has taken suo motu cognizance of media reports on this. Reportedly, the building was unauthorised and constructed more than a decade back. However, the residents were paying taxes to the Vasai-Virar City Municipal Corporation (VVCMC), believing that the building was authorised as per the notarised documents," the NHRC noted.

Accordingly, it has sought a report from Maharashtra's Chief Secretary and Director General of Police, saying that if the reports are true, it raises serious issues of violation of human rights.

"According to a report, a senior officer of the VVCMC has stated that the building might have collapsed due to the use of inferior quality construction material. The residents were sent three notices to vacate the building, but all the warnings were ignored. Reportedly, the building had around 50 flats and half a dozen shops; of which the rear side of the building, comprising around 12 flats, collapsed," the NHRC noted.

Hindustan Times

NHRC takes suo motu cognizance of Nalasopara building collapse

https://www.hindustantimes.com/cities/mumbai-news/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-nalasopara-building-collapse-101756927033101.html

Sept 04, 2025 05:54 am IST Megha Sood

While issuing notices to Maharashtra's chief secretary and director general of Police, NHRC termed the incident a larger violation of human rights and called for a detailed report on the matter within two weeks

MUMBAI: The National Human Rights Commission (NHRC), on Tuesday, took suo motu cognizance of 17 deaths in the Nalasopara building collapse incident on August 27, and issued notices to the chief secretary and the director general of police of Maharashtra, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

The commission observed that, based on media reports, the building was reportedly an unauthorised construction, which was built more than a decade ago. However, the residents were paying taxes to the Vasai-Virar City Municipal Corporation (VVCMC), establishing that the building was authorised as per the notarised documents, the notice highlighted.

While issuing notices to Maharashtra's chief secretary and director general of Police, NHRC termed the incident a larger violation of human rights and called for a detailed report on the matter within two weeks.

In the notice, NHRC quoted a media report, where a senior officer of the VVCMC had stated that the building might have collapsed due to the use of inferior quality construction material and the negligence of the builder and plot owner. The residents were sent three notices to vacate the building, but all the warnings were ignored, the official told the media.

Deccan Herald

NHRC writes to Maharashtra govt seeking probe in 'Halal lifestyle township' issue

https://www.deccanherald.com/india/maharashtra/nhrc-writes-to-maharashtra-govt-seeking-probe-in-halal-lifestyle-township-issue-3713019

05 September 2025, 00:52 IST Mrityunjay Bose

"The allegations made in the complaint prima facie seem to be serious violations of the human rights of the victims," the NHRC said in the notice issued to Maharashtra's Chief Secretary under section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

Mumbai: In a shocking development, a housing project in Karjat, Raigad, the district neighbouring the financial capital of Mumbai, has advertised a "Halal lifestyle township" leading to a major controversy even as the National Human Rights Commission (NHRC) has shot off a letter to the Maharashtra government seeking a probe and an Action Taken Report (ATR).

NHRC member Priyank Kanoongo has flagged the issue and posted the advertisement video on X microblogging platform.

"This is not an advertisement but spreading poison. In the Karjat area near Mumbai, a township with halal lifestyle is being built exclusively for those of the Muslim faith. This is a nation within the nation," he wrote.

"We are issuing a notice to the Maharashtra government asking whether it is granting permission to create separate settlements for Muslims in Maharashtra, the land of Chhatrapati Shivaji Maharaj. This matter is not just about creating a separate township. The advertisement is being done in such a way that it suggests Muslims are facing intolerance and want to move to a separate place to protect themselves," he said.

The project is known as "Sukoon Empire."

In the advertisement, a lady is seen saying: "When you are forced to compromise on your family's principles in society, is that right? At Sukoon Empire, you will find authentic community living, like-minded families sharing the same values, children growing safely in a Halal environment, and elders being respected and cared for. This investment secures not just your money, but also your family's future."

The issue has gone viral on social media platforms.

"The allegations made in the complaint prima facie seem to be serious violations of the human rights of the victims," the NHRC said in the notice issued to Maharashtra's Chief Secretary under section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

"The NHRC Registry is directed to issue notice to Chief Secretary, Government of Maharashtra, with directions to get the allegations made in the complaint inquired

into and to submit an Action Taken Report and directs the authority concerned to submit the provisions under which such permission/license for the township has been granted by the RERA (Mumbai, Maharashtra) based on religion, which threatens the sovereignty, integrity, and unity of India," the notice said.

Janta se Rishta

NHRC ने विरार इमारत हादसे पर महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी

https://jantaserishta.com/local/maharashtra/nhrc-seeks-report-from-maharashtra-government-on-virar-building-collapse-4248646

4 Sept 2025 4:35 PM Tara Tandi

Mumbai मुंबई: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुंबई के पास पालघर जिले के विरार में इमारत ढहने की घटना पर महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी।

पिछले हफ्ते, 27 अगस्त को, पालघर जिले के वसई तालुका के विरार-पूर्व इलाके में नारंगी रोड पर चामुंडा नगर और विजय नगर के बीच स्थित चार मंजिला इमारत, रमाबाई अपार्टमेंट, में 17 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

एनएचआरसी ने कहा, "एनएचआरसी ने इस बारे में मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लिया है। कथित तौर पर, यह इमारत अनधिकृत थी और एक दशक से भी पहले बनी थी। हालाँकि, निवासी वसई-विरार नगर निगम (वीवीसीएमसी) को कर चुका रहे थे, यह मानते हुए कि नोटरीकृत दस्तावेजों के अनुसार इमारत अधिकृत थी।"

इसके अनुसार, आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि अगर ये खबरें सच हैं, तो ये मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती हैं।

एनएचआरसी ने कहा, "एक रिपोर्ट के अनुसार, वीवीसीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इमारत घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के कारण गिरी होगी। निवासियों को इमारत खाली करने के लिए तीन नोटिस भेजे गए थे, लेकिन सभी चेतावनियों को नज़रअंदाज़ कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इमारत में लगभग 50 फ्लैट और आधा दर्जन दुकानें थीं; जिनमें से इमारत का पिछला हिस्सा, जिसमें लगभग 12 फ्लैट थे, ढह गया।"

PIB

NHRC, India organises National Conference on the ‘Rights of Transgender Persons’ in New Delhi

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2163904

04 SEP 2025 8:18PM

Inaugurating it, Chairperson, Justice Shri V. Ramasubramanian says India is far ahead of several other countries in recognising the rights of Trans persons though the societies all over still grappling to accept men and women alone do not constitute the human race

Shri Amit Yadav, Secretary, MoSJE, in his special address says, the Government committed to ensure nobody stands discriminated including the Transgender persons

Shri Bharat Lal, Secretary General, NHRC says, the true measure of the society lies in how it treats its most marginalised and vulnerable communities

NHRC report released on the status of Garima Greh Shelter for transgender person highlights various key concerns for ameliorating the cause of their rights

The National Human Rights Commission (NHRC), India today organised a day long National Conference on the ‘Rights of Transgender Persons: Revamping Spaces, Reclaiming Voices’ at India Habitat Centre in New Delhi. Chairperson, Justice Shri V. Ramasubramanian inaugurated in the presence of Shri Amit Yadav, Secretary, MoSJE, Shri Bharat Lal, Secretary General, NHRC, senior officers, representatives of key Ministries, experts, judicial and legal experts, policy makers, civil society organisations, UN agencies, law enforcement agencies, academicians and community leaders among various stakeholders.

Invoking Isavasya and Chandokya Upanishads, Justice Ramasubramanian said that India is a country where discourse on equality was taken to such great heights by the Upanishads that every unit of creation is God’s manifestation. Therefore, he questioned how can some units of such creations be discriminated by others. He said that these are the pivotal questions around which the NHRC has organised this conference.

He said that if we have a look at the history of evolution of human rights in modern times, everything is in a binary. The mere change of terminology from ‘men’ to ‘human beings’ in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) in 1948 has not actually transformed our stereotypical thought processes and the society continues to think that men and women alone constitute the human race. There could be and there are human beings, who do not fit into this binary of men and women. This is something that the societies all over, are still grappling to accept. He said that the consequences of this is that Trans people experience wide spread discrimination and stigma in the health sector, schools, employment and housing as well as in accessing washrooms.

Justice Ramasubramanian said that fortunately, India is far ahead of several other countries in recognising the rights of Trans persons with the legislative, executive and the judiciary coming together to transform the philosophy of Upanishads into a Constitutional Theme and then to translate the same into a court order followed by a Parliamentary law in the shape of the Transgender Person (Protection of Rights Act, 2019). However, the constitutionality of Sections 4, 5, 6, 7, 12(3), 18(a) and 18(d) are currently under challenge before the Supreme Court of India. It is in this context that the NHRC is privileged to host this National Conference as a segment of our population estimated as per the 2011 census, to be around 4.88 lakh cannot be left out of the mainstream.

Before this, Shri Amit Yadav, Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment (MoSJE), in his special address said that in line with the guiding principles in Article 14, 15 and 16 of the Constitution, the Government is committed to ensure that nobody, including the Transgender persons, is discriminated against. The 2019 Act, enacted post Supreme Court orders, talks about every aspect of their welfare including health, education etc. We have to ensure that the provisions of this Act are translated into action. The setting up of National Council for Transgender Persons, SMILE scheme for Garima Grehs, National Portal for Transgender persons are some of the proactive measures taken by the government towards the welfare of Transgender persons. He said that the improvement and revision of guidelines based on feedback is always a work in progress. Based on the feedback, the Government in 2025 changed the guidelines for the Garima Grehs. For health care also the Government is issuing Transgender Ayush Cards and so far 50 cards have been issued. To expedite this process, he said that the transgender persons need to identify and register themselves on the National Portal. He said that the NHRC, SHRCs, others institutions and civil society can make an important contribution in building awareness about this.

Shri Yadav said that the Government has also started skill and vocational training for them to ensure their employment as per the 2019 Act provisions and the first batch of trained transgender persons is about to complete this training. The Government is also organising Rozgar melas for the Transgender persons. More partnership with private sector is needed for this purpose. The Government is further working on revising their welfare schemes and it is looking forward to suggestions and funds are not a challenge. Their grievance redressal mechanism will be strengthened in the coming months. He said that the MoSJE is also working with the Department of Education to sensitise children about the issues of Transgender persons and build awareness in an effort to collectively work towards their rights for equal opportunity, dignity and inclusivity. Such conferences and forums as organised by the NHRC, India are very important for this purpose.

Earlier, Shri Bharat Lal, Secretary General, NHRC said that human dignity is indivisible and the true measure of the society lies in how it treats its most marginalised and vulnerable communities. He highlighted that in ancient and medieval India, transgender persons were held in high esteem, without any discrimination. Unfortunately, Criminal Tribes Act, 1871 classified the community as a ‘criminal tribe’. An enlightened India after independence, repealed the Criminal

Tribes Act in 1952. Also Section 377 of the erstwhile IPC criminalised ‘non hetero–normative sexual behaviour’, which has become a part of our history.

He said that according to the 2011 Census, approximately 4.88 lakh individuals identified themselves as transgender persons. This is just 0.04% of India’s population. Yet behind these numbers lies a stark reality: a literacy rate of only 56.07% among transgender persons, significantly lower than the national average; limited access to formal employment; and widespread barriers in accessing supportive, gender-affirming healthcare. He said that documentation too remains a major hurdle. Non-availability of ‘gender identity certificates’ continues to block access to welfare schemes, financial services and justice. He said that we must support Transgender children with care, not rejection; ensure dignity and care for elderly Transgender persons; make law enforcement protective allies, not threats; and open up employment opportunities to uphold dignity through independence.

However, Shri Lal also noted that in the last decade, tremendous progress has been made since 2012 the Ministry of Social Justice and Empowerment began working on Transgender issues. He emphasised that for the NHRC, protection and promotion of most vulnerable and marginalised sections of society and their dignity is the top most priority. In 2001-02, NHRC recommended review of Section 377 of then IPC and NDPS Act. In 2018, NHRC constituted Core Group on LGBT issues and the Transgender community has been the focus. In 2020, during Covid–19 pandemic, the Commission issued an Advisory protecting LGBTQ+ community. On 15th September, 2023, the Commission issued an Advisory for ensuring the welfare of Transgender persons. He said that in 2024-25, NHRC team visited 12 Garima Greh Shelters established in the first phase to gather ground level insights and develop evidence–based future course of actions. The findings have been compiled in the form of a report —Transgender Persons: Revamping Spaces, Reclaiming Voices – Insights from Garima Greh Shelters and Beyond. This report was released on the occasion.

Shri Samir Kumar, Joint Secretary, NHRC gave an overview of the Conference and Smt. Saidingpuii Chhakchhuak, Joint Secretary, NHRC delivered the vote of thanks in the inaugural session.

Based on the findings of the Commission’s team, the report emphasises on strengthening of the Garima Greh initiative besides suggesting several key reforms. All states should activate Project Monitoring Committees (PMCs), with clear delegation of responsibilities to district officials and appointment of police focal points for transgender issues. Timely release of funds must be ensured, along with revised allocations for food and beneficiaries, context-specific financial models for urban and rural shelters and infrastructure support through one-time grants. Staffing structures should align with market standards, with rationalised roles to prevent overburdening. Shelter heads must be empowered to assist with transgender ID card issuance through simplified, privacy-sensitive processes. In healthcare, broader medical expenses should be covered, hospital partnerships established and the rollout of Ayushman Bharat TG Plus expedited, alongside stronger mental health and HIV/AIDS services.

The report also recommends employment and skill development, shelter stay should be extended for those pursuing education or exams, vocational training access expanded and shelters linked with job portals, while ensuring workplace protection under the POSH Act. Legal amendments are needed to support gender non-conforming minors, with the establishment of child care and elderly homes for Transgender persons, supported by NGOs. Greater transparency through updated data, strong monitoring and a dedicated ministry desk is essential. These reforms can transform Garima Greh into a foundation for dignity, empowerment and inclusion.

Apart from the inaugural and valedictory sessions, the conference was divided into three technical sessions and a panel discussion. The first session on ‘Strengthening Garima Greh Shelters’ was chaired by Smt. Anita Sinha, Chief Commissioner, Income Tax Department. The panelists were Smt. B. Radhika Chakraborty, Joint Secretary, National Commission for Women, Ms. Isabelle Tschan, Deputy Resident Representative, UNDP, India, Ms. Reshma Prasad, Dostana Safar, Patna and Shri Nikunj Jain, Co-Director, Tapish Foundation, Garima Greh. Second session on ‘Institutional Care for Gender Non Conforming Children & Elderly Transgender Persons’ was chaired by Dr. D.M. Mulay, Former Member, NHRC. The panelists were Smt. Tripti Guha, Additional Secretary, MWCD & Chairperson, NCPCR, Ms. Laxmi Narayan Tripathi, NHRC Special Monitor & Core Group Member, Ms. Abhina Aher, Managing Director, Tweet Foundation and Shri Gopi Shankar Madurai, Intersex and Genderqueer activist, Founder, Srishti Madurai. The third session on ‘Building a Fair and Inclusive Law Enforcement Framework’ was chaired by Smt. Jyotika Kalra, Former Member, NHRC with participation from Ms. Shalini Singh, IPS, Director General of Police, Puducherry, Sh. Ram Dulesh, Dy. Commissioner Police, Delhi, Ms. Kalki Subramaniam, Founder, Sahodari Foundation and Ms. Shreegauri Sawant, Transgender Rights Activist.

After this, a panel discussion on ‘Unlocking Employment, Defying Challenges - Stories of Triumphs’ was chaired by Shri Bharat Lal, Secretary General, NHRC along with participation from Smt. Latha Ganpathy, Joint Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment, Ms. Zainab Patel, Managing Director, Pride Business Network Foundation and Ms. Nishtha Nishant, Manager, Diversity, Equity and Inclusion, Lalit Suri Hospitality Group, Stories of triumphs were shared by Shri Ronit Jha, Sub Inspector, Bihar, Shri Bunty Kumar, Sub Inspector, Bihar and Dr. Beoncy Laishram, Manipur.

In the Valedictory Session, Shri Bharat Lal, Secretary General, while summing up the discussions said that in every session panelists from the Transgender community brought to light the fact that among various marginalised groups, Transgender persons remain the most vulnerable. He stressed the need for concerted efforts, greater investment in education, improved access to healthcare and the creation of more opportunities for their inclusion. While many states have initiated inclusive measures, there is still much room for improvement. He emphasised that the transgender community, civil society and government must work together to uphold constitutional values and achieve true equality, reminding all that dignity must be

extended to everyone. He concluded by noting that while progress has been made, significant work still lies ahead.

Dr. V.K. Paul, Member, NITI Aayog, in his way forward address thanked the NHRC for its outreach and acknowledged the importance of the issue. Referring to the NHRC's report, he praised its coverage of gender non-conforming children, best practices in employment and workplace inclusion. He stressed that awareness must be raised to reinforce the idea that society is one and humanity is indivisible. He further underlined that India must lead the way on Transgender rights, as they are deeply rooted in Indian values. He called for scaling up efforts across all sectors of society, adopting systematic approaches to address gender-related challenges in workplaces and assured that NITI Aayog stands ready to collaborate with the NHRC for any policy interventions and guide in advancing the cause of Transgender persons. Smt. Kim, DIG, NHRC delivered the vote of thanks.

Hindu

Societies grappling to accept those who do not fit into the binary of man or woman, says NHRC chief

https://www.thehindu.com/news/national/societies-grappling-to-accept-those-who-do-not-fit-into-the-binary-of-man-or-woman-says-nhrc-chief/article70012426.ece

September 04, 2025 10:37 pm IST Ishita Mishra

The country cannot grow unless transpersons, whose population is estimated at 4.88 lakh in India as per the 2011 Census, are left out of the mainstream, says Justice Ramasubramanian

Societies all over the world are grappling to accept that there are human beings who do not fit into the binary of man or woman, chairperson of the National Human Rights Commission (NHRC), Justice (retd.) V. Ramasubramanian said on Thursday (September 4, 2025).

Addressing a national conference on transgender rights in Delhi, the NHRC chief added that it is due to the stigma attached to their gender identity that transpeople experience widespread discrimination in the health sector, schools, employment and housing, as well as in accessing toilets.

Quoting the data from the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), the NHRC chief stated that millions of transpersons in all regions experience rejection, harassment and physical violence because they do not conform to prevailing gender norms. He also cited the Trans Murder Monitoring report, a research project of TGEU (Trans Europe and Central Asia), which tracks the murders of trans and gender diverse people globally.

“According to its report released in 2024, there were 350 reported murders during the period from October 1, 2023 to September 30, 2024, of which 12 happened in India. The report also recorded 5,000 cases of such murders since 2008. This report was released on the occasion of the Transgender Day of Remembrance, which is observed annually on November 20, in the memory of those who have been “murdered as a result of transphobia,” said Justice Ramasubramanian.

Citing Hindu religious books, the NHRC chief said that the Upanishads say that every unit of creation is God’s manifestation. He questioned how can some units of creation be discriminated against by others.

“Can one unit of creation be considered inferior to others and can any of such creations be treated with contempt?” he asked, stressing that the country cannot grow unless transpersons, whose population is estimated at 4.88 lakh in India as per the 2011 Census, are left out of the mainstream.

Hailing India for being far ahead of several other countries in recognising the rights of transpersons, the NHRC chief gave credit for the same to the legislative, the executive, and the judiciary.

“These three pillars of democracy have come together, to transform the philosophy of the Upanishads into a constitutional philosophy and then to translate the constitutional philosophy into a parliamentary enactment,” he added.

Hindustan Times

Society struggling to accept humans who don't fit into man-woman binary: NHRC chief

https://www.hindustantimes.com/india-news/society-struggling-to-accept-humans-who-don-t-fit-into-man-woman-binary-nhrc-chief-101756979015525.html

Sept 04, 2025 03:13 pm IST PTI

New Delhi, India is "far ahead" of several other nations in recognising the rights of transgender persons, and while the country "may not have reached an ideal level", but it has certainly advanced to a great extent in this area, NHRC Chairperson, Justice V Ramasubramanian said on Thursday.

In his address at a national conference here, he also said that there could be or that there are human beings who "do not fit into this binary of man or woman" is something that the societies all over, are still grappling to accept.

"The consequence of this, is that trans people experience widespread discrimination and stigma in the health sector, schools, employment and housing as well as in accessing bathrooms," the National Human Rights Commission chairperson said.

The day-long national conference on the rights of transgender persons is being held at the India Habitat Centre here by the NHRC.

Centered on the theme "Revamping Spaces, Reclaiming Voices," the event emphasises "the immediate need to tackle systemic discrimination, uplift lived experiences, and promote meaningful inclusion for transgender persons in all areas of life", the NHRC said.

The rights panel chief began his address by quoting some texts from the Upanishads, which underline that the God pervades in all humans, and all living and non-living beings.

If India is a country where the discourse on equality was taken to such great heights by the Upanishads, and if it is the philosophy of the Upanishads that every unit of creation is God's manifestation, "can some units of such creation be discriminated against by others," the NHRC chief asked.

Can one unit of creation be considered inferior to the others and can any of such creations be treated with contempt, Justice Ramasubramanian emphasised. He said these were the pivotal questions around which this conference has been designed.

"Fortunately, India is far ahead of several other countries in recognising the rights of trans persons. We may not have reached an ideal level, but we have certainly advanced to a great extent," he asserted.

This is because for the first time in history that the three pillars of democracy in India, namely "the legislative, the executive, and the judiciary, have come together, to transform the philosophy of the Upanishads into a constitutional philosophy and then to translate the constitutional philosophy into a parliamentary enactment," he said.

In his address, he also cited some data drawn from Trans Murder Monitoring, a research project of TGEU that tracks the murders of trans and gender diverse people globally.

According to its report released in 2024, there were "350 reported murders during the period from October 1,2023 to September 30, 2024", of which 12 had happened in india, the rights panel's chairperson said.

This report also recorded the 5,000th recorded case of anti-trans murders since the year 2008. This report was released on the occasion of the Trans day Remembrance which is observed annually on November 20 to memorialise those who have been "murdered as a result of transphobia," he added.

He also underlined the change in wordings of texts of global declarations pertaining to human rights, equality and justice, over the centuries.

But the mere change of terminology from 'man' to 'human beings' has "not actually transformed our stereotypical thought processes, and the society continues to think that men and women alone constitute the human race," the NHRC chief said.

"That there could be and that there are human beings who do not fit into this binary of man or woman, is something that the societies all over, are still grappling to accept," he added.

The NHRC is privileged to host this national conference as "a huge segment of our population, estimated as per the 2011 census, to be around 4.88 lakh cannot be left out of the mainstream," the chairperson said.

A comprehensive report aimed at strengthening policies and frameworks to uphold the rights and dignity of transgender persons, was also released on the occasion.

Times Now

Trans People Continue To Suffer Discrimination, Stigma: NHRC Chief

https://www.timesnownews.com/india/trans-people-continue-to-suffer-discrimination-stigma-nhrc-chief-article-152674489

Sep 5, 2025, 00:42 IST Harish V Nair

In the thought process of large sections, its still that only men and women constitute the human race, said Justice V Ramasubramanian.

New Delhi: "Ishaa Vaasyam Idam Sarvam Yat Kincha Jagatyaam Jagat, Tena Tyaktena Bhunjeethaa Maa Grudhah Kasya-svit Dhanam," this is how NHRC Chairperson, Justice V Ramasubramanian began his speech at the National Conference on Rights Of Transgender Persons 'Revamping Spaces, Reclaiming Voices' on Thursday.

Quoting the Isavasya Upanishads, Justice Ramasubramanian said the whole Universe is enclosed or enveloped in God. And also, He dwells or resides in the entire Universe. So, God is in everything and everything is clothed within God. Whatever is moving (or not moving) in this Universe, is all penetrated and also enclosed by Him. All that is living or non-living, pleasing or otherwise, planets, stars or even our Self, the Atma, is pervaded by him.

“Sarvam kalvidam brahma," means all this is Brahman. Everything comes from Brahman, everything goes back to Brahman, and everything is sustained by Brahman, says Chandokya upanishad.

“If India is a country where the discourse on equality was taken to such great heights by the Upanishads, and if it is the philosophy of the Upanishads that every unit of creation is God’s manifestation, can some units of such creation be discriminated against by others? Can one unit of creation be considered inferior to the others and can any of such creations be treated with contempt? he asked.

“These I think are the pivotal questions around which this conference has been designed by the National Human Rights Commission of India”, he said.

Mere change of terminology from ‘men’ to ‘human beings’ has not actually transformed our stereotypical thought processes and the society continues to think that men and women alone constitute the human race, he said.

That there could be and that there are human beings who do not fit into this binary of man or woman, is something that the societies all over, are still grappling to accept. The consequence of this, is that Trans people experience widespread discrimination and stigma in the health sector, schools, employment and housing as well as in accessing bathrooms.

"Fortunately, India is far ahead of several other countries in recognising the rights of trans persons. We may not have reached an ideal level, but we have certainly advanced to a great extent," he asserted.

This is because for the first time in history that the three pillars of democracy in India, namely "the legislative, the executive, and the judiciary, have come together, to transform the philosophy of the Upanishads into a constitutional philosophy and then to translate the constitutional philosophy into a parliamentary enactment," he said.

In his address, he also cited some data drawn from Trans Murder Monitoring, a research project of TGEU that tracks the murders of trans and gender diverse people globally.

According to its report released in 2024, there were "350 reported murders during the period from October 1,2023 to September 30, 2024", of which 12 had happened in india, the rights panel's chairperson said.

This report also recorded the 5,000th recorded case of anti-trans murders since the year 2008. This report was released on the occasion of the Trans day Remembrance which is observed annually on November 20 to memorialise those who have been "murdered as a result of transphobia," he added.

He also underlined the change in wordings of texts of global declarations pertaining to human rights, equality and justice, over the centuries.

But the mere change of terminology from 'man' to 'human beings' has "not actually transformed our stereotypical thought processes, and the society continues to think that men and women alone constitute the human race," the NHRC chief said.

"That there could be and that there are human beings who do not fit into this binary of man or woman, is something that the societies all over, are still grappling to accept," he added.

The NHRC is privileged to host this national conference as "a huge segment of our population, estimated as per the 2011 census, to be around 4.88 lakh cannot be left out of the mainstream," the chairperson said.

Hindu

Transgender children, senior citizens need special shelter homes: NHRC

https://www.thehindu.com/news/national/transgender-children-senior-citizens-need-special-shelter-homes-nhrc/article70013435.ece

September 04, 2025 11:26 pm IST - Ishita Mishra

Garima Greh shelters currently provide residential support for transgender people between the ages of 18 and 60 only; funding delays, inexperienced staff, insufficient food hamper shelters, says NHRC

Trans people under 18 years and above 60 years should be housed in special shelter homes, the National Human Rights Commission (NHRC) recommended on Thursday (September 4, 2025), in a report on the Garima Greh, shelters for transgender people which are run by NGOs with funding from the Union Ministry of Social Justice and Empowerment.

The Commission also found irregularities in the funds released to these special shelters, along with complaints of inexperienced staff and inadequate food for their residents.

NHRC secretary general Bharat Lal released the report, titled, ‘Rights of transgender persons — Revamping spaces, reclaiming voices’, which is based on the visit of an NHRC team to 12 such shelter homes in nine States. The team’s aim was to gather ground-level insights and develop evidence-based future courses of action for improvement in these shelter homes, he said.

Minors, elderly excluded

The Garima Greh shelters currently provide residential support for transgender people between the ages of 18 and 60, and are not permitted to house minors. However, as the only State-backed institutions for transgender individuals, these shelters frequently receive requests to accommodate gender nonconforming minors as well, the report said.

It suggested that the government establish child care institutions for trans children who face lifelong challenges that often intensify with age, as they experience compounded vulnerabilities stemming from social, economic, and healthcare disparities.

The report also highlighted the lack of dedicated shelter homes and welfare schemes specifically designed for elderly transgender people and recommended that separate shelter homes be opened for them as well.

“Current policy does not cater to gender non conforming children under the [Juvenile Justice] JJ Act or elderly transgender persons, leaving both age groups vulnerable,” the report said.

Funding delays

Documenting the delays in funds for the shelter homes, inadequate food and living allowances, limited government-supported premises, eviction threats, and poor living conditions, including a lack of privacy, which undermine shelter sustainability, the report recommended timely fund distribution and a check on the other loopholes.

The Commission also found that other challenges, such as overburdened staff, non-functional Project Monitoring Committees (PMCs) in States like West Bengal, lack of police sensitivity, and impractical reporting requirements, weaken the management of these homes.

Hindustan

ट्रांसजेंडर लोगों को स्वीकार नहीं कर रहा समाज : एनएचआरसी

https://www.livehindustan.com/ncr/new-delhi/story-nhrc-chief-advocates-for-rights-of-transgender-and-gender-non-conforming-individuals-in-india-201756996962239.html

Thu, 4 Sep 2025 08:12 PM

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम ने कहा कि भारतीय समाज ट्रांसजेंडर और जेंडर नॉन कन्फॉर्मिंग व्यक्तियों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रहा है। उन्होंने...

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी रामसुब्रमण्यम ने गुरुवार को कहा कि भारतीय समाज अब भी उन लोगों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा है, जो पुरुष-महिला श्रेणी में फिट नहीं बैठते हैं। एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर और जेंडर नॉन कन्फॉर्मिंग व्यक्तियों को अब भी भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जो कि उनके मूलभूत मानवाधिकारों का उल्लंघन है। एनएचआरसी प्रमुख ने सरकार, नागरिक समाज और संस्थानों से आग्रह किया कि वे समावेशी नीतियों, जागरूकता अभियानों और संवेदनशीलता प्रशिक्षण के जरिए एक ऐसा वातावरण तैयार करें जहां हर व्यक्ति को उसकी पहचान के साथ गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिले।

उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, जब तक समाज में सोच नहीं बदलेगी, तब तक असली बदलाव नहीं आएगा।

Punjab Kesari

दिल्ली पहुँचा शारिक मछली का गुर्गा: NHRC सदस्य को मिठाई देकर मनाने की नाकाम कोशिश

https://mp.punjabkesari.in/madhya-pradesh/news/shariq-machli-s-henchman-reached-delhi-2207204

04 Sep, 2025 04:19 PM Himansh Sharma

भोपाल। मध्यप्रदेश में लव जिहाद और ड्रग्स से जुड़े केस में गिरफ्तार आरोपियों शारिक मछली और यासीन मछली को छुड़ाने की साजिश दिल्ली तक पहुँच गई। जानकारी सामने आई है कि शारिक का करीबी एक व्यक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुँचा और आरोपी के पक्ष में बोलने की कोशिश की।

प्रियंक कानूनगो का खुलासा

सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रियंक कानूनगो ने बताया कि मेरे दिल्ली शासकीय आवास पर जैनेंद्र पाठक नामक एक व्यक्ति स्वयं को मध्यप्रदेश का निवासी बता कर मुलाक़ात के लिए आया।

मुझसे मिलकर बोला कि “वो भोपाल वाले शारिक मछली के साथ प्रॉपर्टी का धंधा करता है व उसकी तरफ़ से आया है उसका बहुत नुक़सान हो गया है उसको छोड़ दीजिए।”

मैंने उसको डाँट कर भगा दिया ,वो अपने साथ लाई मिठाई देना चाह रहा था जो कि वो जाते वक्त घर के दरवाजे पर छोड़कर भाग गया।

गौरतलब है कि शारिक मछली पर कई गंभीर केस दर्ज हैं। उस पर आरोप है कि वह हिंदू युवतियों को नशे के जाल में फँसाकर बलात्कार करता था, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था और जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करता था। इसके अलावा, अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों के पारंपरिक तालाबों पर कब्जा कर मत्स्य व्यवसाय चलाने की शिकायतें भी जांच के दायरे में हैं।

कानूनगो ने स्पष्ट किया है कि इन मामलों की जाँच निष्पक्षता और सख्ती से की जाएगी और किसी भी तरह के दबाव या प्रलोभन का असर नहीं होगा।

Punjab Kesari

पटना में 10 साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या, फिर पेड़ पर लटकाया शव; NHRC ने लिया संज्ञान

https://bihar.punjabkesari.in/national/news/nhrc-takes-cognizance-of-the-rape-and-murder-of-a-10-year-old-girl-in-bihar-2206929

04 Sep, 2025 11:39 AM Swati Sharma

Bihar Crime News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बिहार के पटना जिले के मनेर इलाके में दस वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तथा जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

लकड़ी इकट्ठा करने गई थी पीड़िता

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया है कि 26 अगस्त को बिहार के पटना जिले के मनेर क्षेत्र में एक बगीचे के रखवाले ने 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। बताया गया है कि अपराधी ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए पीड़िता के शव को एक पेड़ पर लटका दिया। पीड़िता लकड़ी इकट्ठा करने गई थी, तभी अपराधी उसे अमरूद का प्रलोभन देकर बगीचे के पास एक कमरे में ले गया और दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी। आयोग ने पाया कि मीडिया रिपोर्ट यदि सत्य है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला बनता है।

इस संबंध में आयोग ने बिहार के पुलिस महानिदेशक और पटना के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट और मृतक के परिजनों को दिए गए मुआवजे का विवरण मांगा है। 31 अगस्त, 2025 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, लड़की के लापता होने की रिपोर्ट उसके परिवार ने 26 अगस्त, 2025 को दर्ज कराई थी और बाद में 28 अगस्त, 2025 की सुबह उसका शव पानी से भरे बगीचे में एक पेड़ से लटका हुआ बरामद किया गया था। इस मामले में आरोपी भोला राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

Jagran

पटियाला आवारा कुत्ते के मुंह में शिशु का सिर मिलना मामला: मानवाधिकार आयोग ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट

https://www.jagran.com/punjab/patiala-human-rights-commission-seeks-report-on-infants-head-found-with-stray-dog-in-patiala-24035281.html

Thu, 04 Sep 2025 12:58 PM (IST) Suprabha Saxena

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पटियाला में सरकारी राजिंदरा अस्पताल के पास आवारा कुत्ते द्वारा शिशु का कटा हुआ सिर ले जाने की घटना पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव और एसएसपी को दो सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। अस्पताल प्रशासन ने शिशु के लापता होने की बात से इनकार किया है।

जागरण संवाददाता, पटियाला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकारी राजिंदरा अस्पताल के पास आवारा कुत्ते द्वारा एक शिशु का कटा हुआ सिर ले जाने की घटना का कड़ा नोटिस लिया है।

इस संबंध में पंजाब सरकार के मुख्य सचिव व पटियाला के एसएसपी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें बताया था कि 26 अगस्त को पटियाला के सरकारी राजिंदरा अस्पताल के पास एक आवारा कुत्ता शिशु का कटा हुआ सिर ले जाता हुआ देखा गया था।

अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा था कि अस्पताल से कोई भी शिशु लापता नहीं हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई सभी बच्चों की मृत्यु के मामलों में, उचित दस्तावेजों के बाद शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं।

The Print

पुरुष-महिला श्रेणी में फिट नहीं बैठने वालों को समाज स्वीकार करने में कर रहा संकोच : एनएचआरसी प्रमुख

https://hindi.theprint.in/india/society-is-hesitant-to-accept-those-who-do-not-fit-into-the-male-female-category-nhrc-chief/864253/?amp

4 September, 2025 Ravi Kant Naresh

नयी दिल्ली, चार सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी रामसुब्रमण्यन ने बृहस्पतिवार को कहा कि तृतीय लिंग (ट्रांसजेंडर) व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता देने में भारत कई अन्य देशों से 'काफी आगे' है।

उन्होंने कहा कि हालांकि देश 'आदर्श स्तर तक नहीं पहुंच पाया है' लेकिन इस क्षेत्र में यह निश्चित रूप से काफी हद तक आगे बढ़ चुका है।

न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने यहां एक राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने संबोधन में यह भी कहा कि समाज में ऐसे मनुष्य हो सकते हैं या हैं जो 'पुरुष या महिला की इस द्विआधारी' श्रेणी में फिट नहीं बैठते।

उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी बात है जिसे दुनिया भर के समाज अभी भी स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

एनएचआरसी के अध्यक्ष ने कहा, "इसका परिणाम यह है कि तृतीय लिंग (ट्रांसजेंडर) लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र, स्कूलों, रोजगार और आवास के साथ-साथ शौचालयों तक पहुंच में व्यापक भेदभाव और कलंक का सामना करना पड़ता है।"

एनएचआरसी द्वारा यहां इंडिया हैबिटेट सेंटर में तृतीय लिंग के व्यक्तियों के अधिकारों पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

मानवाधिकार आयोग के प्रमुख ने अपने संबोधन की शुरुआत उपनिषदों के कुछ उद्धरणों से की, जो इस बात पर जोर देते हैं कि ईश्वर सभी मनुष्यों तथा सभी जीवित और निर्जीव प्राणियों में व्याप्त है।

न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने कहा कि यदि भारत एक ऐसा देश है जहां समानता के विमर्श को उपनिषदों ने इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया, और यदि उपनिषदों का दर्शन यह है कि सृष्टि की प्रत्येक इकाई ईश्वर की अभिव्यक्ति है, तो यह एक बहुत बड़ी बात है।

उन्होंने सवाल किया, "क्या ऐसी रचना की कुछ इकाइयों के साथ दूसरों द्वारा भेदभाव किया जा सकता है?"

न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने इस बात पर जोर दिया कि क्या सृजन की एक इकाई को अन्य से निम्नतर माना जा सकता है और क्या ऐसी किसी भी रचना को अवमानना के साथ देखा जा सकता है?

उन्होंने कहा कि ये वे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके इर्द-गिर्द यह सम्मेलन आयोजित किया गया है।

Navbharat Times

मिठाई लेकर NHRC सदस्य के घर पहुंचा मछली गैंग का 'दूत', पार्टनर बताकर दिया 'डील' का ऑफर, घसीटते हुए ले गई पुलिस

https://navbharattimes.indiatimes.com/state/madhya-pradesh/bhopal/machhli-gang-messenger-reached-nhrc-member-house-with-sweets-offered-deal-by-claiming-to-partner/articleshow/123696534.cms

4 Sept 2025, 3:49 pm Akash Sikarvar

Machhli Gang Offer Priyank Kanungo: एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो के घर एक व्यक्ति खुद को शारिक मछली का पार्टनर बताकर मिलने पहुंचा। शारिक मछली भोपाल के चर्चित मछली गैंग का सरगना है और फरार है। प्रियंक कानूनगो ने व्यक्ति की शिकायत पुलिस में दी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

भोपाल: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भोपाल के मछली परिवार का एक आदमी उनसे दिल्ली में मिला। बता दें कि यह परिवार कई गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है। इनमें ड्रग्स का धंधा, मनी लॉन्ड्रिंग और जबरन धर्म परिवर्तन जैसे आरोप शामिल हैं। कानूनगो के अनुसार, उस आदमी ने अपना नाम जैनेंद्र पाठक बताया। उसने कहा कि वह शारिक मछली का रियल एस्टेट पार्टनर है।

व्यक्ति को डांटकर भगाया

प्रियंक कानूनगो ने बताया कि उस व्यक्ति ने बताया कि वह मछली परिवार की तरफ से आया है। उसने कानूनगो को मिठाई भी दी, लेकिन कानूनगो ने उसे डांटकर भगा दिया। इसके बाद, कानूनगो ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया।

सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख दी जानकारी

कानूनगो ने X पर पोस्ट किया कि भोपाल क्राइम ब्रांच ने शारिक मछली और उसके परिवार के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इन पर ड्रग्स का धंधा करने और हिंदू महिलाओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। कानूनगो ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस मामले की पूरी सख्ती और ईमानदारी से जांच करेगी।'

मछली परिवार पर दर्जनों आरोप

पिछले कुछ हफ्तों में, मछली परिवार के लगभग एक दर्जन सदस्यों पर कई आरोप लगे हैं और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। भोपाल क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। 21 अगस्त को, भोपाल जिला प्रशासन ने मछली परिवार के एक आलीशान बंगले को तोड़ दिया। प्रशासन का कहना है कि यह बंगला सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। इसके अलावा, परिवार की कई संपत्तियां और अवैध कब्जे वाली जमीनें भी जब्त की गई हैं।

भाई-भतीजे की गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई

यह कार्रवाई शाहवर मछली और उसके भतीजे यासीन मछली की गिरफ्तारी के बाद हुई है। इन दोनों पर मध्य प्रदेश में एक ड्रग्स सिंडिकेट चलाने का आरोप है। मछली परिवार मूल रूप से भोपाल के

बुधवारा का रहने वाला है। वे पहले मछली बेचने का काम करते थे। बाद में, वे 1970 और 1980 के दशक में हथाईखेड़ा में बस गए। धीरे-धीरे, परिवार ने स्थानीय नेताओं और प्रभावशाली लोगों से संबंध बना लिए। आरोप है कि इन संबंधों की वजह से वे अपने अवैध धंधों को चलाते रहे। बाद में, उन्होंने मछली पालन, अवैध खनन, जमीन हड़पने और 1990 के दशक तक ड्रग्स और हथियारों की तस्करी जैसे धंधे भी शुरू कर दिए।

Aaj Tak

मिठाई लेकर दिल्ली पहुंचा भोपाल के शारिक मछली का गुर्गा, NHRC मेंबर से बोला- भारी नुकसान हो गया, छोड़ दो उसे

https://www.aajtak.in/madhya-pradesh/story/bhopal-sharik-machli-gang-member-visits-nhrc-fails-to-bribe-lcln-rpti-2325163-2025-09-04

04 सितंबर 2025, 11:41 AM IST Ravish Pal Singh

Delhi News: भोपाल के 'मछली परिवार' पर ड्रग्स की तस्करी और ब्लैकमेलिंग के गोरखधंधे में शामिल रहने के आरोप हैं. यह परिवार न सिर्फ अवैध मादक पदार्थ की आपूर्ति में शामिल रहा है, बल्कि 'लव जिहाद' मामले में छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाने में भी उसकी भूमिका सामने आई है.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर भोपाल के शारिक मछली गैंग से जुड़ा एक शख्स पहुंचा और उन्हें प्रलोभन देने की कोशिश की. लेकिन कानूनगो ने सख्त नाराजगी जताते हुए आरोपी को फटकार लगाई और तुरंत बाहर निकलवा दिया. इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई है.

प्रियंक कानूनगो ने 'X' पर पोस्ट में लिखा, "मेरे दिल्ली सरकारी आवास पर जैनेंद्र पाठक नामक व्यक्ति, जो स्वयं को मध्य प्रदेश का निवासी बता रहा था, मुझसे मिलने आया. उसने कहा कि वह भोपाल के शारिक मछली के साथ प्रॉपर्टी का व्यवसाय करता है और उसकी ओर से आया है. उसने बताया कि शारिक को भारी नुकसान हुआ है और उसे छोड़ दिया जाए. मैंने उसे डांटकर भगा दिया. वह अपने साथ लाई मिठाई छोड़ना चाहता था, जो उसने दरवाजे पर रखकर भागते समय छोड़ दी. हमने पुलिस को शिकायत की, और पुलिस ने मिठाई जप्त कर ली.

शारिक के खिलाफ हिंदू लड़कियों को नशीले पदार्थ देने, बलात्कार, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और इस्लाम में धर्मांतरण कराने के साथ-साथ वंचित केवट-मांझी समुदाय के वंशानुगत तालाबों पर मत्स्याखेट के लिए कब्जा करने के मामलों में मेरे निर्देश पर जांच चल रही है. जांच पूरी सख्ती और निष्पक्षता से की जाएगी."

प्रॉपर्टी सौदे के नाम पर लालच

कानूनगो के मुताबिक, शख्स ने प्रॉपर्टी डील के नाम पर लालच देने की कोशिश भी की. वो अपने साथ मिठाई का डिब्बा भी लाया था और भेंट स्वरूप देना चाहता था. लेकिन उन्होंने सख्ती से इनकार करते हुए आरोपी को बाहर निकलवा दिया. बताया जाता है कि वह मिठाई का डिब्बा दरवाजे पर ही छोड़कर वहां से भाग गया. अब पुलिस ने मिठाई का डिब्बा जब्त कर जांच शुरू कर दी है.

Patrika

मुंबई के करीब बन रही हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप, मचा बवाल, NHRC ने फडणवीस सरकार से मांगा जवाब

https://www.patrika.com/mumbai-news/maharashtra-halal-lifestyle-township-built-near-karjat-nhrc-seeks-response-from-government-19917858

Sep 04, 2025 Dinesh Dubey

Maharashtra Halal Township: एनएचआरसी में दाखिल शिकायत के अनुसार, किसी धर्म विशेष के आधार पर आवासीय परियोजना का निर्माण नहीं किया जा सकता। यह समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

मुंबई से लगभग 70 किलोमीटर दूर कर्जत में बन रही एक टाउनशिप को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस टाउनशिप को 'हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप' (Halal Lifestyle Township) नाम से प्रमोट किया जा रहा है और दावा है कि यह केवल मुस्लिम समुदाय के लिए बनाई जा रही है। इसी वजह से धार्मिक आधार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का दरवाजा खटखटाया गया है। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि इस परियोजना को रेरा मुंबई द्वारा मंजूरी मिली हुई है। आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप

NHRC में दाखिल शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यह टाउनशिप केवल एक धार्मिक समुदाय के लिए है, जो समानता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस तरह की सोसाइटी समाज में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती हैं और इससे सुरक्षा व सामाजिक सौहार्द दोनों को खतरा है।

NHRC ने मांगा जवाब

आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव से दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) मांगी है। साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि रेरा (RERA) ने किस आधार पर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी।

आयोग की सख्त टिप्पणी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने साफ कहा कि धर्म के आधार पर किसी भी आवासीय टाउनशिप को अनुमति देना देश की एकता, अखंडता और संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। अब सबकी निगाहें महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं।

Navbharat Times

मुंबई में बन रही है सिर्फ मुस्लिमों के लिए 'हलाल' सोसाइटी, देखें टाउनशिप का वह वीडियो जिस पर मचा बवाल

https://navbharattimes.indiatimes.com/metro/mumbai/other-news/mumbai-muslims-only-township-project-row-nhrc-member-called-ad-as-poison-issue-notice-halal-lifestyle-project-karjat-know-all/articleshow/123703316.cms

4 Sept 2025, 11:01 pm Achhalendra Katiyar

Mumbai Halal Township Row: मुंबई के पास सिर्फ मुस्लिमों के लिए टाउनशिप की तैयारी से हंगामा खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने धर्म विशेष के लिए सोसाइटी बनाने के लिए नोटिस जारी किया है। यह नोटिस महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को भेजा गया है। NHRC ने दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है।

मुंबई: आपको सुनने में भले अजीब लगे कि कोई बिल्डर सिर्फ धर्म विशेष के लिए टाउनशिप बनाए, जी हां चौंक गए, लेकिन मुंबई के पास कर्जत में एक ऐसी टाउनशिप बन रही है। जो सिर्फ मुस्लिमों के लिए होगी। इस टाउनशिप के विज्ञापन पर बवाल खड़ा हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के एक सदस्य प्रियांक कानूनगो विज्ञापन को विष व्यापन बताया है। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा है कि मुंबई के पास करजत इलाके में केवल मुसलमान मजहब वालों के लिए हलाल लाइफ़ स्टाइल वाली टाउनशिप बनाई जा रही है। यह Nation Within The Nation है।महाराष्ट्र सरकार को नोटिस किया जा रहा है। कानूनगो ने यह नोटिस महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को भेजा है। इसमें पूछा गया है कि कैसे रेरा ने इस एप्रूव कर दिया।

दो हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

कर्जत में जिस हलाल स्पेशल सोसाइटी का निर्माण किया जा रहा है। वह वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस होगी। इसके विज्ञापन में मुस्लिमों को नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने महाराष्ट्र सरकार से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि यह मामला सांप्रदायिक विभाजन और संविधान के उल्लंघन से जुड़ा हो सकता है। मुंबई के पास करजत इलाके में प्रस्तावित एक विशेष टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यह टाउनशिप 'हलाल लाइफस्टाइल' और केवल मुसलमान समुदाय के लिए होने के दावों के कारण सुर्खियों में है

NHRC को मिली है शिकायत

दावा किया जा रहा है कि एनएचआरसी को एक शिकायत मिली थी। इसमें कहा गया है कि एक शिकायतकर्ता ने NHRC को बताया कि करजत में 'हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप' नाम से एक प्रोजेक्ट को प्रमोट किया जा रहा है। आरोप है कि यह आवासीय कॉलोनी सिर्फ एक ही धर्म (मुस्लिम समुदाय) के लिए बनाई जा रही है। इसे धर्म-विशेष के लिए ही आधारित आवासीय क्षेत्र के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने कहा कि यह प्रोजेक्ट न केवल सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देता है। यह संविधान के प्रावधानों, समानता और भेदभाव-निषेध के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है।

कंप्रोमाइज नहीं करने की अपील

सोशल मीडिया पर इस टाउनशिप का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में कहा गया है कि जब सोसाइटी में अपने प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़ें तो सही नहीं है। सुकून इंपायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग। यहां लाइक-माइंडेड फैमिलीज रहेंगी। बच्चे हलाल एनवायरनमेंट में सुरक्षित बड़े होंगे। बुजुर्गों को सम्मान और देखभाल मिलेगी। प्रेयर प्लेसेस और कम्युनिटी गैदरिंग वॉकिंग डिस्टेंस पर होंगे। यह निवेश न सिर्फ आपकी फैमिली बल्कि आपके भविष्य को भी सुरक्षित करेगा। विवाद के बाद डेवलपर की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ यूजर ने इस टाउनशिप की आलोचना करते हुए इस मिनी पाकिस्तान की संज्ञा दे डाली है।

Navbharat Times

विरार बिल्डिंग हादसा: 17 मौतों पर NHRC का संज्ञान, राज्य सरकार और DGP को नोटिस

https://navbharatlive.com/maharashtra/mumbai/palghar-building-accident-nhrc-takes-cognizance-of-17-deaths-notice-to-state-government-and-dgp-1341277.html

Sep 04, 2025 | 07:53 AM Sonali Chavare

Maharashtra News: पालघर के विरार में चार मंजिला इमारत गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार और DGP से इस मामले में जवाब मांगा है।

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पालघर जिले में पिछले महीने हुए दर्दनाक बिल्डिंग हादसे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

यह घटना 27 अगस्त को विरार (पूर्व) इलाके में हुई थी, जब चार मंजिला अपार्टमेंट की इमारत अचानक ढह गई। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जानकारी के मुताबिक, यह इमारत करीब दस साल पहले बनाई गई थी और कथित रूप से अनधिकृत थी।

एनएचआरसी ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि उसने मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने कहा कि मृतकों और घायलों के परिवारजन लंबे समय से इस इमारत में रह रहे थे और वसई-विरार महानगरपालिका (VVMC) को बाकायदा कर (टैक्स) भी चुका रहे थे। निवासियों का मानना था कि नोटरीकृत दस्तावेजों के आधार पर यह इमारत वैध (अधिकृत) थी।

आयोग ने टिप्पणी की कि यदि मीडिया में सामने आई खबरें सही हैं, तो यह मामला गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन को दर्शाता है। नागरिकों को सुरक्षित आवास का अधिकार है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही और घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल ने दर्जनों जिंदगियों को निगल लिया।

बयान में यह भी उल्लेख किया गया कि इमारत के गिरने की एक वजह निर्माण की गुणवत्ता में भारी खामियां हो सकती हैं। 28 अगस्त को सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार, बिल्डिंग संभवतः खराब मटीरियल की वजह से ध्वस्त हुई। अब एनएचआरसी ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और डीजीपी से जवाब तलब किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट में हादसे की जिम्मेदारी तय करने, पीड़ितों को मुआवजा देने और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की पूरी जानकारी शामिल होनी चाहिए।

इस हादसे ने न सिर्फ 17 परिवारों की खुशियां छीन लीं, बल्कि पूरे इलाके में असुरक्षा की भावना भी पैदा कर दी है। सवाल यह है कि आखिर कब तक लोग अपनी ही छत के नीचे असुरक्षित महसूस करते रहेंगे?

NDTV

सिर्फ मुस्लिमों के लिए बन रही थी सोसाइटी! हलाल टाउनशिप पर हुआ बवाल तो NHRC ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

https://ndtv.in/maharashtra-news/karjat-in-maharashtra-karjat-halal-township-in-karjat-9214194

सितंबर 04, 2025 11:40 am IST Samrajeet Singh

NHRC के पास आई शिकायत में कहा गया है कि इस तरह की धर्म आधारित रिहायशी कॉलोनी सीधे तौर पर साम्प्रदायिक चीजों को बढ़ावा देती है और भारतीय संविधान के बराबरी और भेदभाव न करने के सिद्धांत का उल्लंघन करती है.

मुंबई: मुंबई के पास करजत में बनी एक टाउनशिप को लेकर अब विवाद बढ़ता दिख रहा है. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने महाराष्ट्र सरकार को इसे लेकर नोटिस तक जारी कर दिया है. इस पूरे विवाद की वजह है इस टाउनशिप का नाम. आपको बता दें कि यह टाउनशिप सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप के नाम से प्रमोट की जा रही है. इसी वजह से अब इसे लेकर विवाद हो रहा है.

NHRC के पास आई शिकायत में कहा गया है कि इस तरह की धर्म आधारित रिहायशी कॉलोनी सीधे तौर पर साम्प्रदायिक चीजों को बढ़ावा देती है और भारतीय संविधान के बराबरी और भेदभाव न करने के सिद्धांत का उल्लंघन करती है. शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि इस प्रोजेक्ट को RERA (मुंबई) ने मंजूरी दी है, जिससे सुरक्षा और सामाजिक स्तर पर (अलग-थलग करने) का खतरा बढ़ सकता है.

NHRC ने शिकायत को गंभीर मानते हुए महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव से 2 हफ्ते के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि सरकार बताए कि किस प्रावधान के तहत RERA ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी.कमीशन ने साफ किया है कि धर्म के आधार पर ऐसी किसी भी कॉलोनी को लाइसेंस देना देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ है.

News 18

सिर्फ मुस्लिमों के लिए स्पेशल सोसाइटी... क्या महाराष्ट्र को इस्लामिक स्टेट बनाने की है तैयारी? जानें क्या है हलाला टाउनशिप प्रोजेक्ट

https://hindi.news18.com/news/maharashtra/mumbai-nhrc-seeks-report-on-halal-lifestyle-township-project-near-mumbai-calls-allegations-serious-local18-ws-kln-9584282.html

September 04, 2025, 12:57 IST Vivek Gupta & Kunal Jha

मुंबई के पास करजत में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए बनाई जा रही कथित हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप पर विवाद गहराता जा रहा है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने महाराष्ट्र सरकार से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि यह मामला सांप्रदायिक विभाजन और संविधान के उल्लंघन से जुड़ा हो सकता है.

Halal Lifestyle Township Project: मुंबई के पास करजत इलाके में प्रस्तावित एक विशेष टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. यह टाउनशिप 'हलाल लाइफस्टाइल' और केवल मुसलमान समुदाय के लिए होने के दावों के कारण सुर्खियों में है. इस मुद्दे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

शिकायत का आधार

एक शिकायतकर्ता ने NHRC को बताया कि करजत में 'हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप' नाम से एक प्रोजेक्ट को प्रमोट किया जा रहा है. आरोप है कि यह आवासीय कॉलोनी सिर्फ एक ही धर्म (मुस्लिम समुदाय) के लिए बनाई जा रही है और इसे धर्म-विशेष आधारित आवासीय क्षेत्र के रूप में प्रचारित किया जा रहा है.

शिकायतकर्ता ने कहा कि यह प्रोजेक्ट न केवल सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देता है, बल्कि संविधान के प्रावधानों, समानता और भेदभाव-निषेध के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है. साथ ही उन्होंने सुरक्षा और सामाजिक चिंता भी जताई, क्योंकि यह क्षेत्र कट्टरपंथी घेट्टो (गेटोइजेशन) का रूप ले सकता है.

NHRC की प्रतिक्रिया

मानवाधिकार आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है. आयोग ने निर्देश दिया है कि शिकायत की गहन जांच की जाए. यह स्पष्ट किया जाए कि RERA (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) ने इस तरह के प्रोजेक्ट को अनुमति कैसे दी. साथ ही जांच रिपोर्ट (Action Taken Report) दो सप्ताह में आयोग को सौंपी जाए. आयोग ने कहा कि अगर यह प्रोजेक्ट धर्म के आधार पर बनाया जा रहा है, तो यह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा है.

प्रियंक कानूनगो का बयान

NHRC के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर कहा, “यह विज्ञापन नहीं, विष-व्यापन है. मुंबई के पास करजत इलाके में केवल मुसलमानों के लिए हलाल लाइफस्टाइल वाली टाउनशिप बनाई जा रही है. यह ‘नेशन विदिन द नेशन’ है. महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है.”

विवादित वीडियो

सोशल मीडिया पर इस टाउनशिप का एक वीडियो भी वायरल हुआ है. वीडियो में कहा गया है:

“जब सोसाइटी में अपने प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़ें तो सही नहीं है. Sukoon Empire में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग. यहां लाइक-माइंडेड फैमिलीज रहेंगी, बच्चे हलाल एनवायरनमेंट में सुरक्षित बड़े होंगे, बुजुर्गों को सम्मान और देखभाल मिलेगी. प्रेयर प्लेसेस और कम्युनिटी गैदरिंग वॉकिंग डिस्टेंस पर होंगे. यह निवेश न सिर्फ आपकी फैमिली बल्कि आपके भविष्य को भी सुरक्षित करेगा.”

Punjab kesari

सूर्या हांसदा मामले में NHRC ने लिया संज्ञान, गोड्डा के DCऔर SP से मांगी 4 सप्ताह में रिपोर्ट

https://bihar.punjabkesari.in/jharkhand/news/nhrc-took-cognizance-of-surya-hansda-case-sought-report-from-godda-dc-and-sp-2207045

04 Sep, 2025 01:10 PM Harman

Jharkhand News: झारखंड के सूर्या हांसदा केस में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गोड्डा के उपयुक्त और पुलिस अधीक्षक से चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आजसू की तरफ़ से संजय मेहता ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में केस दर्ज करवाया था। आजसू के केंद्रीय महासचिव संजय मेहता के आवेदन पर आयोग ने संज्ञान लिया था।

आयोग ने अब इस मामले में गोड्डा के डीसी, एसपी से चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आयोग की गंभीरता से परिजनों में न्याय की आस जगी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रियांक कानूनगो सदस्य की अध्यक्षता में, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत इस मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने शिकायत में लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना है। इस संदर्भ में आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। आजसू की तरफ़ से संजय मेहता ने 20 अगस्त को आयोग में मामला दर्ज करवाया था। 29 अगस्त को आयोग ने जाँच दल का गठन किया। आयोग ने एनएचआरसी के महानिदेशक (जांच) को निर्देश दिया कि वे एक विशेष जांच दल गठित करें और इस मामले की विस्तृत जांच कर 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आयोग के सहायक रजिस्ट्रार बृजबीर सिंह ने इस बावत महानिदेशक (जांच) को पत्र लिखा। आयोग द्वारा 02 सितंबर को गोड्डा के जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने और चार सप्ताह के भीतर कारर्वाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। आयोग ने गोड्डा पुलिस से स्पष्टीकरण माँगा है।

गोड्डा के पुलिस अधीक्षक को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है कि आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार मुठभेड़ की जानकारी निर्धारित समय के भीतर आयोग को क्यों नहीं दी गई। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। मेहता ने कहा कि हम इस मामले की लड़ाई विधिक और न्यायिक स्वरूप में लड़ रहें हैं। आयोग के संज्ञान और गंभीरता से आस जगी है। आयोग ने चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट माँगी है। आयोग इस मामले में सख़्त है।